उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का योगदान (जनपद इलाहाबाद पर आधारित शोध प्रबन्ध)

Dr. Shailendra Kumar Singh
(Asst. Prof. NGBU Allahabad)

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का सदैव से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और वर्तमान में भी है। पिछले पाँच दशकों के दौरान देश में लघु उद्योग क्षेत्र ने एक मजबूत और स्थिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने मे उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। रोजगार, उत्पादन, निर्यात, संतुलित आर्थिक विकास तथा गरीबी हटाने के दृष्टिकोण से लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष दर्जा–रहा है तथा सरकारी संरक्षण एवं सहायता के अन्तर्गत इनका विकास एवं विस्तार भी होता रहा है। आज इस क्षेत्र में 7,500 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो उत्पाद तैयार करने वाले क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत और कुल निर्यात क्षेत्र का 35 प्रतिशत है, यह क्षेत्र उद्यमियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 'नर्सरी' का काम भी करता है। इसके अलावा यह 30 लाख कारखानों के जरिए देश में औद्योगिक विकास के उत्प्रेरक का भी काम करता है। यह कारखाने देश में कुल कारखानों का लगभग 95 प्रतिशत है। साथ ही ये देश में कुल कारखानों का लगभग 95 प्रतिशत हैं साथ ही ये देश में सबसे अधिक रोजगार भी प्रदान करते हैं। इनमें एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है। इस प्रकार यह रोजगार देने, सभी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, गरीबी हटाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है।

देश में लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा संयन्त्रों और मशीनों में निवेश के आधार पर की जाती है। इसमें जमीन और इमारतों, परीक्षण उपकरणों, प्रदूषण समाप्त करने के उपायों पर लगा निवेश शामिल नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकी सीमा में निरन्तर वृद्धि की गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से मुद्रस्फीति को देखते हुए की गई है और इस समय वह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक करोड़ रूपये और बहुत छोटे उद्योग या ग्रामीण उद्योग के लिए 2.5 लाख रूपये है। सेवा क्षेत्र के लिए यह सीमा पाँच लाख रूपये हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को मोटे तौर पर दो छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्षेत्र आधुनिक लघु उद्योग और दूसरा परम्परागत ग्रामीण उद्योग क्षेत्र है। आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, उत्पादन सुविधा, श्रमिक सघनता, पूंजी गहनता आदि में बड़े और मध्यम उद्योग क्षेत्र की तरह ही होते हैं। परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में हथकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग दस्तकारी, रेशम, नारियल जूट आदि शामिल है। सामान्यतः ये उद्योग दस्तकार आधारित होते है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में स्थिति होतें है। इसलिए इन्हें ग्रामीण उद्योग भी कहते हैं। इनके संयन्त्रों और मशीनों में नाममात्र की पूंजी लगाई जाती है।

लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की ओर नीति निर्माताओं ने स्वतन्त्रता के एक दशक बाद से विशेष ध्यान देना शुरू किया। इसके बावजूद आज भी इन उद्योगों का व्यवस्थित विकास नहीं हो पाया है। सर्वविदित है कि वर्ष 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से एकदम अलग–थलग थी। उस समय इस बात पर जोर दिया जाता था कि अपेक्षित उत्पादन देश में ही किया जाय और देशी उद्योगों की आन्तरिक प्रतियोगिता से लाइसेंस प्रणाली और नियन्त्रण (कंट्रोल) द्वारा तथा विदेशी प्रतियोगिता से आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर और उच्च सीमा शुल्क लगाकर। इस पृष्ठभूमि में सम्पूर्ण और औद्योगिक क्षेत्र का ध्यान देश की जरूरतें पूरी करने में ही ला रहा और निर्यात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना तो की गई मगर उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी निर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के समुचित उपाय नहीं किये गये। अनुसंधान एवं विकास कार्यो तथा लागत घटाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे प्रतियोगिता

लगभग समाप्तप्राय हो गई। परिणाम यह हुआ कि विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी, जो स्वतन्त्रता के समय लगभग दो प्रतिशत भी 1991 में घटकर 0.6 प्रतिशत रह गयी ।

उत्तर – प्रदेश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग चार प्रतिशत अंश पर वसा इलाहाबाद जनसंख्या एवं आकार की दृष्टि से यद्यपि एक महत्वपूर्ण जनपद हैं, लेकिन आर्थिक विकास के आधार पर निश्चित ही एक पिछड़ा जनपद है। साथ ही समस्या को केन्द्र बिन्दु मानते हुए ही प्रस्तुत अध्ययन प्रस्तावित है। स्पस्ट है, कि इस प्ररिप्रेक्ष्य मे अभी तक इस आधार पर कोई भी मूल्यांकन कार्य नहीं हुआ है। अतः जनपद की गरीबी और पिछड़ेपन को मुख्य समस्या मानते हुए ''उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास मे लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का योगदान (जनपद इलाहाबाद पर आधारित शोध प्रबन्ध)'' जैसे विषय को अवश्य ही एक उपर्युक्त अध्ययन विषय माना जाना चाहिए।

प्रस्तावित शोध अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है––

1. जनपद इलाहाबाद में व्याप्त गरीबी, पिछड़ेपन एवं आर्थिक विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालना।
2. जनपद के कृषि क्षेत्र से श्रमिकों के पलायन को रोकने और कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाकर श्रमिकों की आय में वृद्धि करने और निवेश के स्तर को बढ़ाने के प्रयासों का मूल्यांकन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र जनपद इलाहाबाद में सन्तुलित एवं त्वरित क्षेत्रीय आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने के लिए नये औद्योगिक वातावरण निर्माण की दृष्टि से लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की सकारात्मक भूमिका का आंकलन करना।
4. कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के उत्थान एवं विकास के आधार पर जनपद की ग्रामीण गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन एवं नीतिगत उपायों की समीक्षा करना।
5. जनपद इलाहाबाद के औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक वित्त के पर्याप्त एव सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु संरचनात्मक परिवर्तनों और कार्यशील उपायों का अध्ययन एवं मूल्यांकन।
6. जनपद के गरीबी निवारण कार्यक्रमों का लघु एवं ग्रामीण उद्योगों द्वारा सृजित आय, रोजगार पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना।

प्रस्तावित अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं को परखने का प्रयास किया जायेगा।

1. जनपद इलाहाबाद में व्यापक स्तर पर गरीबी विद्यमान है।
2. आर्थिक विकास की दृष्टि से इलाहाबाद एक पिछड़ा जनपद है।
3. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों द्वारा सृजित आर्थिक विकास और गरीबी निवारण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध विद्यमान है।
4. स्थानीय प्रौद्योगिक व स्वदेशी शोध पर आधारित लघु एवं ग्रामीण उद्योग सदैव गरीबी निवारण और आर्थिक एवं त्वरित ग्रामीण विकास में सहायक होते हैं।
5. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना व विस्तार से जनपद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और रहन–सहन का स्तर ऊपर उठा है।
6. दूसरे जनपदों की तुलना में इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास को अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो रही है।
7. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए सरकारी प्रयास अपर्याप्त है।
8. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की सम्पूर्ण आंकलित क्षमता का प्रयोग गरीबी निवारण एवं आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सका है।

प्रस्तावित शोध अध्ययन एक प्रयोग सिद्ध अध्ययन है। इस अध्ययन के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद के आर्थिक विकास के लिए लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाना है। इस अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का

प्रयोग किया जायेगा ताकि विश्लेषण को यथार्थपरक बनाया जा सके। द्वितीय आंकड़ों के संग्रह हेतु जनपदीय, सांख्यिकीय पत्रिका, राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ भारत सरकार उद्योग मन्त्रालय, लघु उद्योग विकास बैंक (सिडवी) से प्राप्त आवश्यक सूचनायें, विधानसभा की कार्यवाहियों में प्रस्तुत लघु एवं ग्रामीण बैंकों की प्रतिवेदन रिपोर्ट, निष्पादन रिपोर्ट, अनुसंधान एवं शोध संस्थान के प्रकाशन, पत्र–पत्रिकाओं तथा अन्य सम्बन्धित साहित्य का उपयोग किया जायेगा। गरीबी निवारण एवं आर्थिक विकास के सन्दर्भ में लघु एवं ग्रामीण उद्योग कहां तक प्रभावी रहे है, इसका मूल्यांकन करने के लिए जनपद में स्थापित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित सम्बन्धित रिपोर्टों को प्रमुख आधार मानकर प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। तत्पश्चात स्थापित संकल्पनाओं की प्रमाणिकता को सत्यापित किया जायेगा। चूँकि आर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण अध्ययन के दो प्रमुख बिन्दु है। अतः लघु उद्योगों द्वारा लाभ, आय और रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन, निवेश, बचत और पूंजी निर्माण की स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तावित अध्ययन के आधारभूत बिन्दु होंगें। प्रदेश स्तर पर संचालित गरीबी निवारण के कार्यक्रमों की सफलता और असफलता का ब्यौरा भी अध्ययन के शोध उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता सिद्ध होगें। प्रदेश स्तर पर आर्थिक विकास की व्यक्तिगत एवं समष्टिगत विवेचना की जायेगी। यह अपेक्षित है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध जनपद इलाहाबाद के आर्थिक विकास में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की भूमिका हेतु निर्धारित विभिन्न शोध उद्देश्यों के प्रकाश से स्थापित संकल्पनाओं पर खरा उतरेगा।

अध्ययन की सरलता को आधार मानकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का अध्ययन काल यद्यपि 1990 से लेकर 2000 है, तथापि आठवीं (1992–97) एवं नवीं पंचवर्षीय (1997–2002) योजनाओं का समयान्तराल (1997–2002) जो एक दशक होता है, ही अभीष्ट अवधि है। जनपद इलाहाबाद के आर्थिक विकास सम्बन्धित आंकड़ें इस समयान्तराल में सहज उपलब्ध है। निश्चित ही एक अवधि इलाहाबाद जनपद में आर्थिक विकास कार्यक्रमों की पृष्ठिभूमि में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए एक पर्याप्त समयावधि है।

निष्कर्ष –

इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है और जनपद की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या अपनी आजीविका के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की आय भी निम्न है, फलस्वरूप उनका जीवन स्तर भी निम्न कोटि का है। जनपद की अर्थव्यवस्था में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण है।

जनपद के संतुलित एवं त्वरित आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये नयी लघु एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों का वातावरण तैयार करने के लिये लघु औद्योगिक योजनायें बनायी जा रही है। जिनका मुख्य उद्देश्य जनपद में कार्यरत रहने के साथ ही साथ नयी लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु प्रयास करना। जनपद में वर्तमान समय में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट सेवाओं की उपलब्ध कराया गया है साथ ही औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों में भी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि स्थापित लघु एवं ग्रामीण उद्योग टिक सकें और जनपद का समन्वित आर्थिक विकास सम्भव हो सके। जिन तहसीलों एवं सामुदायिक विकास खण्ड़ों में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना नगण्य के बराबर है वहां पर इन उद्योगों के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले प्रथम उद्यमियों का अधिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।

विभिन्न संस्थाओं के अधीन कार्यशील लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 1992–2002 के बीच की समयावधि में व्यक्तिगत उद्योगपतियों, पंजीकृत संस्थाओं, औद्योगिक, सहकारी समितियों द्वारा ही अधिकांश इकाईयों की स्थापना की गयी इसी समयावधि में पंचायत द्वारा एवं क्षेत्र–समिति द्वारा एक भी इकाई की स्थापना नहीं की गयी। लघु उद्योग इकाइयों की स्थिति भी लगभग इसी तरह की थी।

यदि 1992–2002 के बीच जनपद स्तर पर रोजगार की संख्या पर ध्यान दें तो यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की इकाईयों का औसत रोजगार 4.55 था जबकि लघु उद्योग का औसत रोजगार 4.53 व्यक्ति प्रति इकाई था। इसी समयावधि में लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिइकाई उत्पादन का स्तर 348040.71 रूपयें था।

जनपद में यदि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकेन्द्रीकरण विकासखण्ड़ों के आधार पर किया जाय तो तालिका से स्पष्ट है कि जनपद के विकासखण्ड़ों में स्थापित पंजीकृत कारखानों लघु उद्योग इकाईयों और ग्रामीण इकाईयों की स्थापना में बहुत ही असमानता पायी गयी है। पंजीकृत कारखानों की अधिकतम स्थापित संख्या करछना में है जहां 62 इकाईयां हैं। चाका में 26, सोरांव में 12, फूलपुर में 4 इकाईयों की स्थापना की गयी है। कुछ विकासखण्ड़ों में पंजीकृत कारखानों की संख्या एक भी नहीं है। वर्ष 2002–2003 के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि फूलपुर में सबसे ज्यादा 52 लघु इकाईयां, बहादुरपुर में 33 इकाईयां, सैदाबाद में 28 इकाईया, उरूवन में 22 इकाईयां, सोरॉव में 20 इकाईयां स्थापित की गयी है। शेष विकास खण्ड़ों में कुछ ही इकाईयों की स्थापना की गयी है।

तालिका 1.1

जनपद में पंजीकृत कारखाने, लघु औद्योगिक इकाईयाँ, खादी ग्रामोद्योग इकाईयाँ एवं उनमें कार्यरत व्यक्ति (संख्या)

वर्ष / विकासखण्ड	पंजीकृत कारखाने		लघु औद्योगिक इकाईयाँ		खादी ग्रामोद्योग इकाईयाँ	
	कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति	इकाईयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति	इकाईयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2000–01	211	6264	58	269	3162	15743
2001–02	211	6264	546	1011	3210	16198
2002–03	185	17431	680	1524	9131	16622
विकासखण्डवार 2002–03						
1. कौड़िहार	5	75	2	3	35	889
2. होलागढ़	0	0	8	16	74	794
3. मऊअइमा	2	860	17	31	63	713
4. सोरांव	11	220	20	45	83	818
5. बहरिया	0	0	0	0	56	630
6. फूलपुर	4	1955	52	143	82	664
7. बहादुरपुर	8	444	33	90	86	651
8. प्रतापपुर	0	0	11	30	77	638
9. सैदाबाद	2	22	28	60	88	698
10. धनुपुर	0	0	4	12	136	1052
11. हंडिया	2	25	9	25	6280	1317
12. जसरा	1	447	0	0	24	476
13. शंकरगढ़	0	0	5	12	44	364
14. चाका	26	1677	2	6	79	600
15. करछना	62	4943	8	30	883	1095
16. कौंधियारा	0	0	3	9	47	279
17. उरूवन	0	0	22	60	39	224
18. मेजा	0	0	18	54	265	1223
19. कोरांव	0	0	11	33	108	831
20. माण्डा	0	0	0	0	31	118
योग ग्रामीण	123	10668	253	659	8580	14274
योग वन क्षेत्र	—	—	—	—	—	—
योग नगरीय	62	6763	427	865	551	2348
योग जनपद	185	17431	680	1524	9131	16622

स्रोत– जिला उद्योग केन्द्र, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, इलाहाबाद, सांख्यिकी पत्रिका, इलाहाबाद

अध्ययन क्षेत्र में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं का विवरण निम्नवत् है–

लघु एवं ग्रामीण उद्योग स्थानीय कच्चेमाल तथा स्थानीय अकुशल श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी उद्योग इस स्तर पर तभी सफल हो सकता है जब तक कि उस उद्योग को वहां के समाज द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार न कर लिया जाय। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों में जागरूकता की कमी, कुशल श्रमिकों का अभाव तथा आपसी सामजस्यता की कमी है इसका कारण है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च–स्तर पर निरक्षरता व्याप्त है।
2. ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को उद्यम से सम्बन्धित किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव रहता है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का बोलवाला होता है।
5. ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन की प्रवृत्ति
6. बिजली की समस्या, जो कि प्लांट को उनकी क्षमता से कम उत्पादन करने को मजबूर करती है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चेमाल का अभाव तथा उपलब्ध कच्चेमाल की गुणवत्ता में कमी।

सुझाव–

जनपद के आर्थिक विकास को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नवत् सुझाव विचारणीय है–

1. केन्द्र/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को इन उद्योगों को स्थापित करने वाले क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं से सम्बन्धित जैसे यातायात, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा, संचार व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाना चाहिये।
2. ऐसे कच्चे मालों की पूर्ति जिनका अभाव है को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिये तथा विशेष प्रकार की विपणन व्यवस्था करनी चाहिये।
3. जनपद के लीड़ बैंकों को अपनी तरफ से ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिये कार्य योजना बनानी चाहिये।
4. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिये सरकार को चाहिये कि अपने विभागों में इन क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं के क्रय को प्राथमिकता देनी चाहिये।
5. वित्तीय संस्थाओं को चाहिये कि इन उद्योगों के लिये सुविधाजनक साख की व्यवस्था करें।
6. कच्चे मालों और आयातों पर छूट देना चाहिये।
7. बैंकों को गैर–निष्पादनकारी सम्पत्ति की दरों में कमी करनी चाहिये।
8. सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी के निवेश पर लाभ प्राप्त करने के लिये चयनित क्षेत्रों में समान विपणन संगठन की स्थापना करनी चाहिये।

लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, उनका विकास एवं सम्बन्धित समस्याओं के संबंध में सलाह देने का कार्य लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किया जाता है लेकिन आवश्यकतानुसार यह पर्याप्त नहीं है। इन संस्थाओं हेतु ऐसी सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये और कुछ ऐसी ही दूसरी सलाहकारी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये।

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को अपनी पुरानी तकनीक छोड़कर नवीन तकनीक अपनानी चाहिये इससे उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुऐं मिल सकेंगी।

2. लघु उद्योगों की बृहद उद्योगों से प्रतियोगिता में नुकसान होता है लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये कुछ उत्पादन क्षेत्र रखे जा सकते है। अथवा एक सीमा तक ही वृहद उद्योगों के उत्पादन की छूट दी जाय जिससे कि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का भी बाजार मांग की पूर्ति का अवसर मिल सके।
3. उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है कृषि को आधारभूत क्षेत्र मानते हुये ही लघु एवं ग्रामीण उद्योगों तथा इससे सम्बन्धित व्यवसायों को संगठित करना चाहिये। कृषि मूलक लघु एवं ग्रामीण उद्योगों से ही उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण आर्थिक विकास सम्भव है, इससे गरीबी की भयावहता पर भी प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।
4. लघु उद्योग व हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योगों द्वारा परिसज्जा पैकेजिंग प्रक्रिया तथा नये औजार तथा पुर्जो के विकास के कार्यो को औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ अधिक तालमेल स्थापित करके सुदृढ़ करना चाहिये।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, ''दत्त एवं सुंदरम'' पृष्ठ 457
2. उत्तर प्रदेश एवं उद्योग 2000 मजूमदार एस0एच0, पृष्ठ 7, 8
3. योजना, 2001 ''लघु उद्योग औचित्य एवं भविष्य'' पी0सी0 जैन, पृष्ठ 7
4. योजना नवम्बर 2000, ''छोटे एवं मझोले उद्योगों को निर्यातोन्मुखी बनाना, बी0डी0 जेधरा'' पृष्ठ 21।
5. गांधी एम0के0 ''इकोनामिक ऑफ विलेज इण्डस्ट्रीज 1948'', अहमदाबाद पृष्ठ 21।
6. शर्मा दिनेश चन्द्र, राज्य एवं उद्योग, पृष्ठ 254।
7. मिश्रा पुरी, 16वां संस्करण, 2004, पृष्ठ 437।
8. उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर, इलाहाबाद, 1992, पृष्ठ 1।
9. उत्तर प्रदेश, पृष्ठ 747, 2003।
10. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर, पृष्ठ 19।
11. डॉ0 त्रिपाठी, बी0बी0 भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन एवं विकास पृष्ठ 309।
12. उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण–2001–02, पृष्ठ 133।
13. बाबा डी0एस0, रूरल प्रोजेक्ट प्लानिंग, के0सी0 विस्ट, राज्य एवं उद्योग।
14. योजना दिसम्बर 2000।

वार्षिक रिपोर्ट–

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार खादी ग्रामोद्योग कमीशन का वार्षिक प्रतिवेदन 1996 – 2004
2. जनपद सांख्यिकीय पत्रिका इलाहाबाद
3. जिला सामाजिक पत्रिका इलाहाबाद
4. उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास एवं प्रगति 2005 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0
5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्रगति एवं समीक्षा उद्योग, निदेशालय कानपुर 2003
6. जिला खादी ग्रामोद्योग की रिपोर्ट
7. योजना मासिक पत्रिका वर्षवार
8. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका